भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *297

दिनांक 20.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल प्रबंधन में प्रौद्योगिकी-आधारित समाधानों को एकीकृत करने में 'अर्घ्यम' की भूमिका

***297. सुश्री बाँसुरी स्वराजः**
श्री मितेश पटेल (बकाभाई):

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) जल प्रबंधन में प्रौद्योगिकी-आधारित समाधानों को एकीकृत करने में 'अर्घ्यम' की भूमिका क्या है और इससे जल, स्वच्छता और सफाई के क्षेत्र में निर्णय लेने पर किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा;
(ख) इस भागीदारी के तहत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के विकास से जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन का कार्यान्वयन किस प्रकार बढ़ेगा;
(ग) प्रस्तावित डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख तकनीकी घटक क्या हैं और उनसे सतत् जल प्रबंधन और स्वच्छता सेवाओं में किस तरह योगदान मिलेगा; और
(घ) जल परिसंपत्तियों का कुशल संचालन और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए इस पहल के तहत राज्य संस्थानों को किस प्रकार सुदृढ़ किए जाने का विचार है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री
(श्री सी आर पाटिल)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

****

जल प्रबंधन में प्रौद्योगिकी-आधारित समाधानों को एकीकृत करने में 'अर्घ्यम' की भूमिका के संबंध में सुश्री बाँसुरी स्वराज और श्री मितेश पटेल (बकाभाई) द्वारा पूछे गए दिनांक 20.03.2025 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *297 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): अर्घ्यम, एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) है, जो डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के विषयगत क्षेत्र में एक प्रमुख भागीदार के रूप में रूरल वॉश (जल और स्वच्छता, साफ-सफाई) पार्टनर्स फोरम (आरडब्ल्यूपीएफ) में शामिल हो गया है। यह जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत सृजित की गई परिसंपत्तियों का कुशल, टिकाऊ संचालन करने में राज्यों को समर्थ बनाने हेतु डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) के निर्माण में उनके प्रयासों में सहायता/मार्गदर्शन करेगा। डीपीआई राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन के लिए विकसित की जा रही अवधारणा है। इसके बाद, डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान (एसपीएम-निवास) ने अर्घ्यम के साथ एक गैर-वित्तीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया है। यह भागीदारी पेयजल क्षेत्र के लिए डीपीआई को अपनाने के लिए दिशानिर्देश और कार्यनीति तैयार करने के लिए है। यह पहल ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) और इंटरऑपरेबल समाधानों के विकास पर केंद्रित है, जिससे इस क्षेत्र में डेटा-आधारित निर्णय लिया जा सकेगा।

(ग): डीपीआई के प्रमुख तकनीकी घटक में मुख्य रूप से ओपन एपीआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग शामिल हैं।

(घ): डीपीआई ओपन एपीआई और मूलभूत डिजिटल उपकरण प्रदान करता है जिसका लाभ राज्य जल आपूर्ति प्रणालियों की अधिक प्रभावी ढंग से निगरानी, प्रबंधन और रखरखाव के लिए उठा सकते हैं। इन डिजिटल उपकरणों का निर्माण करके, राज्य संदर्भ-विशिष्ट समाधान विकसित कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि प्रणालियां अंतर-संचालनीय और टिकाऊ दोनों हैं।

****